उत्तर प्रदेश

विशिष्ट करेंट अफेयर्स

सितंबर 2022

उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान पर

• 2 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश बाजरा के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बाजरा का उत्पादन होता है, जो देश में कुल बाजरा उत्पादन का 19.69 प्रतिशत है।

• उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भारत के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है।

• उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बाजरा और अन्य पोषक-अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिये कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 की कार्य योजना अन्य के साथ-साथ उत्पादन, खपत, निर्यात और ब्रांडिंग को बढ़ाने की रणनीतियों पर केंद्रित है।

सिंचाई के लिये नाली के पानी का इस्तेमाल करेगी उत्तर प्रदेश सरकार

• 3 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को प्रदेश में फसलों की सिंचाई के लिये नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने के निर्देश दिये।

• जल शक्ति मंत्री ने यह सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया कि नाली का पानी नदियों में न गिरे और इसका उपयोग सिंचाई के लिये किया जाए।

• इससे नदियों में प्रदूषण नहीं बढ़ेगा और साथ ही सिंचाई की लागत में भी काफी कमी आएगी। इससे सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले पानी का संरक्षण करने में भी मदद मिलेगी।

• राज्य में बहने वाले 848 नालों की निगरानी के लिये अधिकारियों को निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि नालों की निगरानी के लिये 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए। नालों के आसपास रहने वाले और समाज से जुड़े लोगों को समिति का सदस्य बनाया जाए।

• उन्होंने कहा कि नमामि गंगे विभाग राज्य भर में चल रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के कार्यों को भी देखेगा।

• नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने इंजीनियरों को निर्देश देते हुए कहा कि वे इस महीने से गंगा की ज़मीन पर सीसीटीवी सर्विलांस लागू करें और कंट्रोल रूम से हर एसटीपी की 24 घंटे निगरानी करें।

देवरिया के खुर्शीद अहमद 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' से सम्मानित

• 5 सितंबर, 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2022 से सम्मानित किया।

• उल्लेखनीय है कि इस वर्ष देश भर से 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चुना गया था, जिनमें उत्तर प्रदेश से एकमात्र शिक्षक खुर्शीद अहमद भी शामिल थे।

• राष्ट्रपति द्वारा खुर्शीद अहमद को सम्मानस्वरूप रजत पदक, 50 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि का चेक और प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

• देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहवा के खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिये दिया गया है। प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों में अकेले इनका चयन हुआ है।

• गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

अब यूरोप और मिडिल ईस्ट तक महकेगा कन्नौज का इत्र

• 6 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत कन्नौज के इत्र को वैश्विक बाज़ार में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार अगले साल फरवरी में पहली बार इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेज़बानी करेगी, जिसमें इत्र उद्योग में अग्रणी फ्राँस समेत यूरोप और मिडिल ईस्ट समेत तमाम अग्रणी देशों के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया जाएगा।

• इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल में विभिन्न देशों के आगंतुकों को कन्नौज के इत्र के निर्माण की प्रक्रिया, इसमें इस्तेमाल होने वाले मूल इनग्रेडिएंट्स समेत अन्य खूबियों से परिचित कराया जाएगा।

• यह फेस्टिवल कन्नौज के इत्र निर्माताओं और उद्यमियों को विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार के लिये मंच उपलब्ध कराएगा। इसके ज़रिये कन्नौज के इत्र कारोबारियों को भी अपने उत्पादों को विदेशी खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने व वैश्विक व्यापार की संभावनाओं को टटोलने का मौका मिलेगा।

• जानकारी के मुताबिक, इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल के लिये विदेशी प्रतिनिधिमंडल को लाने की ज़िम्मेदारी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) की होगी।

• इस आयोजन के तहत लखनऊ में एक दिन का कार्यक्रम होगा, जिसमें विभिन्न सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सभी विदेशी मेहमानों को कन्नौज ले जाया जाएगा। यहाँ उन्हें इत्र के उद्यमियों, इत्र निर्माताओं व निर्यातकों से मिलने का मौका मिलेगा।

एससी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में आय सीमा समाप्त

• 11 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अनुगम) के चेयरमैन डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि अनुगम की स्वरोज़गार योजनाओं का लाभ लेने के लिये अधिकतम आय सीमा की शर्त को खत्म कर दिया गया है।

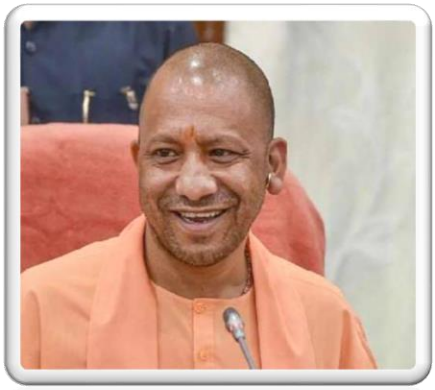

• चेयरमैन डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ले सकेगा, लेकिन ढाई लाख रुपए तक सालाना आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।

• स्वरोज़गार की इकाई समूह में स्थापित करनी होगी और अनुदान की सीमा भी प्रति लाभार्थी 10 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अनुगम की योजनाओं में पात्रता के लिये अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 47,080 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए वार्षिक आय सीमा थी।

• गौरतलब है कि जुलाई 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आय और अनुदान सीमा में वृद्धि के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया था। इसी के तहत केंद्र सरकार ने पात्रता के लिये आय सीमा और अनुदान राशि में बड़ा बदलाव किया है।

• चेयरमैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएँ अब 'प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना'के नाम से जानी जाएंगी। केंद्र व प्रदेश सरकार ने दलित दंश समाप्त करने के लिये महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुँचाकर दलितों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये यह बड़ा कदम उठाया है।

उत्तर प्रदेश में बनेंगे 18 नए थाने और 22 पुलिस चौकियाँ, कुशीनगर में खुलेगा पर्यटन थाना

• 14 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न ज़िलों में पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक मज़बूत बनाने के लिये 18 नए थाने और 22 चौकियाँ बनाने एवं कुशीनगर में नया पर्यटन पुलिस थाना खोलने का फैसला किया है।

• संजय प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, अपराधों पर और अधिक प्रभावी तरीके से अंकुश लगाए जाने, महिलाओं तथा आम लोगों को और अधिक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य के विभिन्न ज़िलों में 18 नए थाने और 22 चौकियाँ बनाने का निर्णय लिया गया है।

• इस संबंध में पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक (पुलिस मुख्यालय) को ज़रूरी आदेश जारी कर दिये गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के इन नए थानों और पुलिस चौकियों में ज़रूरी पदों के सृजन के बारे में अलग से निर्देश जारी किये जाएंगे।

• गाज़ियाबाद ज़िले के मसूरी/कविनगर थाने के क्षेत्र को काटकर वेब सिटी के नाम से तथा विजय नगर थाने के क्षेत्र को काटकर क्रासिंग रिपब्लिक नाम से नए थाने बनाए गए हैं। खम्पर और बांकाटा थाने के बँटवारे के बाद देवरिया में सुरोली नया थाना होगा।

• अयोध्या के मवई थाने का क्षेत्र काटकर बाबा बज़ार नाम से नया थाना बनाया गया है। राजधानी लखनऊ के मलीहाबाद थाना क्षेत्र के रहीमाबाद गाँव में स्थापित पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर रहीमाबाद नाम से नया थाना बनाया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र में एयरपोर्ट थाने की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश के पहले तैरते सोलर संयंत्र से विद्युत उत्पादन शुरू

• 15 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले के दिबियापुर में एनटीपीसी में कई चरणों में हुई जाँच के बाद 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। इससे एनटीपीसी औरैया संयंत्र की कुल क्षमता बढ़कर 704 मेगावाट हो गई है।

• एनटीपीसी के अपर महाप्रबंधक संजय बाल्यान ने बताया कि यह तैरता सोलर संयंत्र प्रदेश में पहला है। एनटीपीसी अब तक चार प्रदेशों- तेलंगाना के रामागुंडम, केरल के कायमकुलम, गुजरात के कवास और आंध्र प्रदेश के सेमाद्री में जलाशय पर तैरते सोलर संयंत्र लगा चुकी है।

• गौरतलब है कि औरैया में फ्लोटिंग सोलर संयंत्र के लिये एनटीपीसी ने सितंबर 2019 में निविदा आमंत्रित की थी। निविदा पाने वाली कंपनी ने जून 2020 में सोलर संयंत्र का काम शुरू किया था। अगस्त 2022 में सोलर प्लांट लगकर तैयार हो गया। इसके बाद टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम पूरा किया गया।

• दिबियापुर स्थित एनटीपीसी में 500 वाट क्षमता के सोलर पैनलों का प्रयोग किया गया है। फ्लोटिंग सोलर संयंत्र की कुल लागत लगभग 90 करोड़ रुपए है।

• एनटीपीसी संयंत्र परिसर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 20 मेगावाट क्षमता का ज़मीन पर सोलर संयंत्र लगाया गया। ज़मीन पर लगे सोलर प्लांट में 330 वाट के सोलर पैनल मॉड्यूल लगाए गए हैं। इस संयंत्र से व्यावसायिक बिजली उत्पादन तीन चरणों में (पहले चरण में 10 नवंबर, 2020 को आठ मेगावाट, 4 दिसंबर, 2020 को सात मेगावाट एवं 20 फरवरी, 2021 को पाँच मेगावाट) ग्रिड से जोड़कर शुरू किया जा चुका है।

मुरादाबाद मंडल में बनेगा नंदी अभयारण्य

• 19 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडलायुक्त आन्जनेय सिंह ने बताया कि आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिये मुरादाबाद मंडल में नंदी अभयारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है।

• राज्य में गायों के रखरखाव के लिये बड़ी संख्या में गोशालाएँ बनाई गईं हैं तथा उनकी व्यवस्था सुधारी गई है, लेकिन नंदियों की देखभाल का कोई इंतजाम नहीं हो सका। इस समस्या के समाधान के क्रम में इन अभयारण्यों की स्थापना की योजना बनाई गई है।

• मंडलायुक्त ने बताया कि मुरादाबाद मंडल के तीन ज़िलों- संभल, अमरोहा और बिजनौर में इसकी पहल की जा रही है। यहाँ नंदी अभयारण्य की स्थापना का काम शुरू कर दिया गया है।

• इन अभयारण्य में नंदी बिना किसी डर के घूम सकेंगे। इसके लिये फिलहाल यहाँ आसपास करौंदा के पेड़ लगाए जाएंगे। इसके बाद बाँस समेत कई ऐसे पौधे लगाए जाएंगे, जिनसे आमदनी भी होगी।

• नंदी अभयारण्यों की आय के अपने स्रोत होंगे, जिससे इनके संचालन में किसी तरह की समस्या भविष्य में न हो। नंदियों को चरने के लिये चारागाह और घास की व्यवस्था भी होगी।

• तीनों ज़िलों में सफलतापूर्ण संचालन के बाद इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। सबकुछ ठीक रहा तो भविष्य में इस तरह के अभयारण्य आवारा पशुओं से प्रभावित अन्य ज़िलों में बनाए जा सकेंगे।

• नंदियों को एक स्थान पर लाकर, उनके लिये भयमुक्त वातावरण के साक्षी यह नंदी अभयारण्य बनेंगे। पेड़-पौधों और घास के बीच नंदी विचरण करेंगे। पीने के पानी के लिये अगर कोई जलाशय होगा, उससे भी इन अभयरण्यों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही ट्यूबवेल का भी इंतजाम किया जाएगा।

उन्नाव के नवाबगंज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव

• 20 सितंबर, 2022 को कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के नवाबगंज में जेवर से भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है।

• दिल्ली-एनसीआर की तर्ज़ पर लखनऊ-कानपुर राज्य राजधानी क्षेत्र में तीन और शहरों- सीतापुर, रायबरेली तथा हरदोई को भी शामिल किया गया है। इससे पहले लखनऊ और कानपुर के अलावा उन्नाव और बाराबंकी शहर ही शामिल थे।

• केडीए के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट बनने के लिये लगभग 10 हज़ार एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होगी। ज़मीन को चिह्नित करने का कार्य शुरू हो गया है।

• सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में लगभग 9 महीने लगे हैं। नवाबगंज के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना इसलिये भी ज़रूरी है, क्योंकि अमौसी एयरपोर्ट का विस्तार अब और नहीं हो सकता।

• शासन के निर्देश पर केडीए ने राज्य राजधानी क्षेत्र के तहत जो कॉन्सेप्ट प्लान बनाया है, उसमें नवाबगंज पक्षी विहार से एयरपोर्ट की न्यूनतम दूरी 5 किमी. रखी गई है, ताकि पक्षियों के हैबीटेट पर कोई असर न पड़े।

• इस एयरपोर्ट का फायदा न सिर्फ राज्य राजधानी क्षेत्र, बल्कि बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश तक के लोगों को मिलेगा।

मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की आयु में हुआ निधन

• 21 सितंबर, 2022 को मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के AIIMS अस्पताल में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उनका बीते 41 दिनों से इलाज चल रहा था, जहाँ उन्होंने उपचार के दौरान अंतिम सांस ली।

• राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते समय दिल का दौरा पड़ने के बाद नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था। वह तब से लाइफ सपोर्ट पर थे और उनमें सुधार के कुछ लक्षण भी दिखे थे।

• जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर, 1963 को हुआ था। उनका असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था, जिन्हें पेशेवर रूप से राजू श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है। राजू श्रीवास्तव को अक्सर 'गजोधर भइया'के नाम से जाना जाता है।

• राजू श्रीवास्तव एक भारतीय हास्य अभिनेता, अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। 2014 से वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। मार्च 2019 में उन्हें उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

• वे 1980 के दशक में हिन्दी फिल्म उद्योग में काम करने के लिये मुंबई चले गए। उन्होंने बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा, आमदनी अठन्नी खरचा रुपैया आदि फिल्मों में अभिनय किया।

• वे कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज'में उपविजेता बने। उन्होंने इसके स्पिन-ऑफ शो 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज-चैंपियंस'में 'द किंग ऑफ कॉमेडी'का खिताब जीता।

उत्तर प्रदेश के छह ज़िलों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज

• 22 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने वायबलिटी गैप फंडिंग (VGF) स्कीम के तहत प्रदेश के छह ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की सैद्धांतिक सहमति दी है।'एक ज़िला एक मेडिकल कॉलेज' (One District One Medical College) कार्यक्रम के तहत यह कार्य किया जाएगा।

• 'एक ज़िला एक मेडिकल कॉलेज'कार्यक्रम के तहत पीपीपी मोड पर महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज संचालन के लिये टेंडर के माध्यम से निवेशकों का चयन किया जाएगा।

• उत्तर प्रदेश में 16 ज़िलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं। छह ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोलने में लगभग 1525 करोड़ रुपए खर्च आएगा। केंद्र सरकार इसमें 1012 करोड़ रुपए सब्सिडी देगी। एक कॉलेज को औसतन 160 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी।

• आलोक कुमार ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी मिलाकर 65 मेडिकल कॉलेज हैं। केंद्रीय संस्थानों में रायबरेली और गोरखपुर में दो एम्स, एक बीएचयू और एक अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज है।

• प्रदेश के अमेठी, औरैया, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, गोंडा, कानपुर देहात, कौशांबी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, पीलीभीत, सोनभद्र और सुल्तानपुर ज़िले को 2022-23 तक मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। इनका निर्माणकार्य चल रहा है।

• है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नौ ज़िलों देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाज़ीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया था।

उत्तर प्रदेश विधानसभा से CRPC संशोधन विधेयक पास

• 23 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 बिल पास कर दिया। इसके तहत अब दुष्कर्म व प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेज एक्ट (पॉक्सो) के मामलों में आरोपित को अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) नहीं मिलेगी।

• संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित करने का प्रस्ताव रखा। विधेयक के पक्ष में सत्ताधारी सदस्यों के बहुमत के कारण विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा की।

• गौरतलब है कि 22 सितंबर को राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया गया था।

• विधेयक के प्रावधान के तहत अब रेप के आरोपियों को अग्रिम ज़मानत नहीं मिलेगी। इस संशोधन विधेयक में CRPC की धारा 438 में बदलाव के साथ ही पॉक्सो एक्ट और 376, 376-A, 376–AB, 376–B, 376-C, 376-D, 376-DA, 376-DB, 386-E की धाराओं में आरोपी को अग्रिम ज़मानत नहीं देने का प्रावधान किया गया है।

• न सिर्फ रेप और गैंगरेप बल्कि यौन अपराध, बदसलूकी और यौन अपशब्द के मामलों में भी अग्रिम ज़मानत नहीं मिल सकेगी।

• हालाँकि, इस कानून को लागू करने पर अभी केंद्र सरकार की मुहर लगना अनिवार्य है क्योंकि इसके लिये गृह मंत्रालय की मंज़ूरी ज़रूरी है।

प्रयागराज में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार

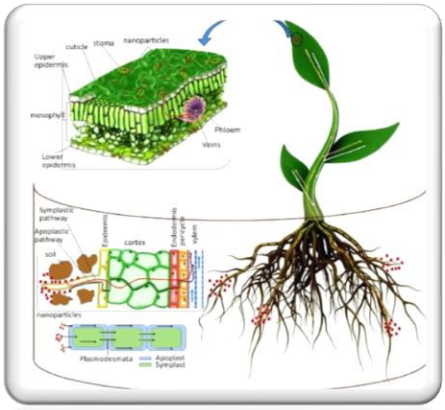

• 25 सितंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज के फूलपुर में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार हो गया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही इससे उत्पादन आरंभ हो जाएगा। नवंबर में इस प्लांट के चालू होने की उम्मीद है।

• देश में इफको का फूलपुर स्थित यह दूसरा प्लांट होगा। इफको की देश में पहली नैनो खाद की इकाई गुजरात स्थित कलोल में लगी थी। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया था।

• दूसरे चरण में आँवला (बरेली) और फूलपुर (प्रयागराज) में इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। फूलपुर प्लांट की उत्पादन क्षमता सात करोड़ और आँवला की क्षमता 11 करोड़ बोतल प्रतिवर्ष है।

• फूलपुर में नवंबर से अगले वर्ष मार्च के बीच 70 लाख बोतल खाद उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तीनों प्लांटों से इफको ने सालाना 32 करोड़ बोतल नैनो यूरिया के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो 37 करोड़ मीट्रिक टन सब्सिडी वाले यूरिया की जगह लेगा।

• फूलपुर यूनिट के हेड संजय कुदेशिया ने बताया कि प्लांट में नैनो फर्टिलाइजर लिक्विड तैयार किया गया है जिसका नवंबर से उत्पादन आरंभ हो जाएगा। इस खाद से मौजूदा समय में यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से नष्ट होती उर्वराशक्ति को बचाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही किसानों का पैसा, परिश्रम और समय भी बचेगा।

• फूलपुर प्लांट में तैयार आधा लीटर नैनो खाद की उर्वरक क्षमता यूरिया की 45 किग्रा. वजनी एक बोरी के बराबर होगी। इसकी आपूर्ति के लिये अर्जेंटीना और ब्राज़ील ने भी इफको से करार किया है।

‘राज्य योजना आयोग’ हुआ अब ‘राज्य परिवर्तन आयोग’

• 27 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसका नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया।

• उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य परिवर्तन आयोग (एसटीसी) का नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे जबकि वित्त मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, कृषि मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, पंचायती राज विकास मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, जल शक्ति मंत्री और शहरी विकास मंत्री इसके सदस्य होंगे।

• एसटीसी के उपाध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या सामाजिक वैज्ञानिक होंगे। अन्य सदस्यों में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त, कृषि, ग्रामीण विकास, चिकित्सा और स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और योजना सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव शामिल हैं।

• आयोग में गैर-सरकारी सदस्य भी होंगे, जो सामाजिक क्षेत्र, कृषि और अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ होंगे। इन मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

• ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि यह आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद नीतियाँ तैयार करेगा। राज्य जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उनकी आयोग द्वारा पहचान की जाएगी और उनके समाधान के तरीके खोजे जाएंगे। पीपीपी मॉडल के इस्तेमाल पर भी चर्चा की जाएगी। वर्तमान योजना और उनके परिणाम का मूल्यांकन आयोग द्वारा किया जाएगा।

• गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त, 1972 को हुई थी और इसने राज्य सरकार को आवश्यकता आधारित क्षेत्रों की पहचान करके नीतियाँ बनाने में मदद की।

उत्तर प्रदेश में एमएसएमई नीति-2022 लागू

• 29 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विभाग ने एमएसएमई नीति-2022 को लागू करने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया। यह नीति सितंबर 2027 तक प्रभावी रहेगी।

• एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में निवेश करने वाले उद्यमियों को दो करोड़ रुपए तक के कोलेटरल फ्री ऋण (यानी बिना गिरवी के ऋण) पर बैंकों की ओर से ली जाने वाली वन टाइम गारंटी फीस राज्य सरकार वहन करेगी।

• नए सूक्ष्म उद्योग के लिये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम 25 लाख रुपए) प्रति इकाई पाँच वर्षों के लिये दिया जाएगा।

• उद्यमियों को पूंजीगत निवेश पर 10 से 25 फीसदी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ऋण के ब्याज पर 60 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।

• बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्रों में क्रमश: 25, 20 और 15 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में क्रमश: 20, 15 और 10 प्रतिशत होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति व महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाएगी।